POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जून, 2025 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा पर ही हमारा जीवन सुरक्षित है। विचार करें, आज हमारे पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। जितना है वह भी प्रदूषित है। वन सम्पदा घटती जा रही है। वनों में रहने वाले जीव-जन्तु जिनका पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह भी खत्म होते जा रहे हैं। हवा भी प्रदूषित है। ऐसे में हम कैसे बचे रह सकते हैं?

इस दिन हम पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते हैं। क्या कभी यह सोचा है कि हम बाकी बचे 364 दिनों में क्या करते हैं। लालच और धन कमाने की लालसा हमारे संकल्पों की धज्जियां उड़ाती हैं। पेड़ों की कद्र करना भूल जाते हैं। यह अन्दाजा नहीं लगाते कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक पेड़ हमें अपने जीवनकाल में जितनी सेवाएं देता है, उसकी कीमत करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए होती है। एक पेड़ को काटने से कितना नुकसान भुगतना पड़ता है, हम सभी को इस पर ध्यान देना होगा।

हमारे पूर्वज पर्यावरण के संरक्षण के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। तभी उन्होंने अपना स्वस्थ्य जीवन पाया। आज हम अनेक बीमारियों के शिकार हैं। हमारा स्वास्थ्य लड़खड़ाता जा रहा है। पीने के पानी की समस्या विकट हो चली है। श्वांस लेने को हवा भी शुद्ध नहीं मिल पा रही। बढ़ता प्लास्टिक का उपयोग और उससे उपजा प्रदूषण हमारे लिए विकट समस्या बन चुका है।

धरती, आकाश, हवा, पानी और ऊर्जा इन पांच तत्वों से हमारा यह शरीर बना है। इनके संतुलन से ही पर्यावरण संरक्षण संभव है। हम सभी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर हम खुद का और अपनी संतानों का सुरक्षित भविष्य कायम रख सकेंगे।

पंचायती राज: शिकायतों की जांच के लिए 10 से 30 दिन की सीमा तय

पंचायती राज में भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए गड़बड़ी की शिकायतों पर 10 दिन से एक महीने में जांच की सीमा तय कर दी है। गड़बड़ी की शिकायत पर जांच व कार्रवाई नहीं होने पर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तय समय सीमा में जांच नहीं करने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरतलब है, पंचायती राज में हर माह औसत 3 से 4 हजार शिकायतें दर्ज होती है।

विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों को लटकाकर रखने के मामलों को देखते हुए यह सर्कुलर जारी किया गया है।

सर्कुलर के मुताबिक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में तय समय सीमा में जांच नहीं करने के कारण दोषी बच जाते हैं। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने वाले सरपंचों सहित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को पहले निलंबित करना होगा। इसके बाद दोष साबित होने पर पद से हटाया जाएगा। पंचायत के सरपंच, उप सरपंच प्राथमिक जांच में दोषी हों तो उनके निलंबन के प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजे जाएंगे।

जॉब कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसे व्यक्तिगत लाभ के मामलों में पद के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच अब 10 दिन में पूरी करनी होगी। पट्टों और निर्माण के कामों में गड़बड़ी की जांच 15 दिन में करनी होगी। निर्माण कामों, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच 30 दिन में पूरी करनी होगी।

भारी पड़ा फिल्म के बीच विज्ञापन दिखाना

फिल्म थियेटर में फिल्म के दौरान पहले दिखाए जाने वाले लंबे विज्ञापनों से परेशान बेंगलुरु के अभिषेक एमआर ने पीवीआर और आइनॉक्स के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में परिवाद दाखिल कर 65 हजार रुपए का मुआवजा जीता है। मामले के अनुसार अभिषेक 2023 में विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर देखने उक्त थियेटर में गए थे। फिल्म से पहले दिखाए गए लंबे विज्ञापनों के कारण फिल्म देरी से शुरू हुई। उन्होंने दावा किया कि इससे उसके लगभग 30 मिनट बर्बाद हो गए और इससे वे एक जरूरी अपॉइंटमेंट में नहीं पहुंच सके, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता अदालत ने माना कि हर व्यक्ति का समय मूल्यवान है। थियेटर में गैर जरूरी विज्ञापन देखने के लिए 25-30 मिनट काफी लंबा समय है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके शेड्यूल काफी व्यस्त होते हैं। इस अनोखे मामले में उपभोक्ता अदालत ने अभिषेक के पक्ष में फैसला सुनाया और फिल्म थिएटर चेन को आदेश दिया कि वह उन्हें 65,000 रुपए का मुआवजा अदा करें।

पंचायती राज को बनाना होगा ताकतवर

लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंचायती राज को ताकतवर बनाने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक राजनेता जमकर वकालत करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी प्रदेश की कोई ग्राम पंचायत 'ए' क्षेणी में जगह नहीं बना पाई।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही वित्त वर्ष 2022-23 के अध्ययन के आधार पर पंचायत उन्नति सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है। जिसमें प्रदेश की 11207 ग्राम पंचायतों में से 10634 ग्राम पंचायतों ने आंकड़े पेश किए। जिनमें से प्रदेश की 1580 पंचायतें बी-श्रेणी में, 8876 सी-श्रेणी में और 178 ग्राम पंचायतों को डी-श्रेणी में रखा है। हाल ही राज्य सरकार नई ग्राम पंचायतों का भी गठन कर रही है। माना जा रहा है, सरकार पंचायती राज को सशक्त बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

पंचायतों में खुलेंगे बर्तन बैंक

प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पारंपरिक आयोजनों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करने, समाज में एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 'बर्तन बैंक योजना' के रूप में एक अभिनव पहल कर रही है। गौरतलब है, बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की गई थी।

प्रदेश में पहला स्टील बर्तन बैंक कोटा जिले में खैराबाद पंचायत समिति में शुरू किया गया है। इसमें 900 सेट स्टील बर्तन रखे गए हैं। योजना के तहत प्रथम चरण में एक हजार पंचायतों को एक-एक लाख रुपए के स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की अन्य पंचायतों में भी बर्तन बैंक प्रारंभ किए जाएंगे। बर्तन बैंक स्थापित करने के लिए पंचायत एवं महिला स्वयं सहायता समूह का चयन 'पहले आओ पहले पाओ' की तर्ज पर किया जाएगा।

पैदा होंगी बछिया, बढ़ेगा दूध उत्पादन

दूध की मांग पूरी करने के लिए बछड़े की जगह बछिया ही जन्म ले, इसके लिए पशुपालन विभाग सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत एक लाख डोज की आपूर्ति करवा रहा है। इसके अलावा एक लाख डोज की आपूर्ति के नये कार्यादेश भी जारी किए गए हैं।

करीब 250 रुपए की डोज पर पशुपालकों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस डोज से कृत्रिम गर्भाधान कराने से 90 प्रतिशत मामलों में बछिया का जन्म होगा। योजना के तहत पशुपालक आसानी से यह कृत्रिम गर्भाधान करा सकेंगे। इससे नर गोवंश की जन्मदर घटेगी। वहीं, दुधारू पशुओं की उन्नत नस्ल का विकास हो सकेगा।

नहीं मिला प्रसूति योजना का लाभ

प्रदेश में श्रम विभाग की प्रसूति सहायता योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिर्फ 11 प्रतिशत पंजीकृत महिला श्रमिकों तक ही पहुंचा। प्रचार-प्रसार की कमी के चलते 89 प्रतिशत महिला श्रमिक इस योजना के लाभों से वंचित रह गए।

इस योजना के तहत 17,850 महिला श्रमिकों को लाभ देने का लक्ष्य था, लेकिन 1,832 महिलाओं को ही फायदा मिल सका। श्रम विभाग की प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए और बेटे के जन्म पर 20,000 रुपए दिए जाते हैं, ताकि मां और शिशु की सेहत सुनिश्चित हो। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही से लक्ष्य कागजों तक ही सिमट कर रह गया।

घर पर ही खुल रहे रोजगार के द्वार

प्रदेश के कई जिलों में ग्रामीण पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही प्रचार-प्रसार होने से ग्रामीण परिवार घर की रसोई में बना खाना पूरी आवभगत से

विदेशी पावणों को खिला रहे हैं। इन परिवारों की कमाई भी अच्छी हो रही है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

जयपुर जिले में ग्रामीण पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी पर्यटकों को आस-पास के जैसे सामोद, कानोता, कालवाड और सांभर के ग्रामीण घर काफी पसंद आ रहे हैं। इन इलाकों में रोजगार के नए द्वार भी तेजी से खुल रहे हैं। करीब 100 से भी ज्यादा परिवार घर बैठे पर्यटकों की मेहमानी कर हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं। ज्यादातर पर्यटकों को बाजरे, मक्का व बेजड़ की रोटी, कैर-सांगरी व खेतों में उगाई ग्रीन वेजिटेबल सब्जियां परोसी जा रही है।

खेत की मिट्टी की होगी देखभाल

मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनके खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए सिफारिश करता है। किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के 41 जिलों के 355 ब्लॉक में 5 लाख 39 हजार मृदा के नमूनों का विश्लेषण करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अब तक पूरे देश में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं और विभिन्न राज्यों को 1706.18 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। देश में 8272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है।

ग्राम पंचायतों में होगी 'फल वाटिका'

पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'मॉडल पंचायत फल वाटिका' विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा पौधे रोपने की योजना भी तैयार की गई है।

ग्यारह हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में विकसित होने वाली इन वाटिकाओं में प्रत्येक में एक-एक हजार पौधे लगाए जाएंगे। इनमें आम, अमरूद, नींबू, आंवला जैसे पारंपरिक और औषधीय गुणों से भरपूर फलों के पौधे भी शामिल होंगे। ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन भेज दी है। पौधारोपण का काम एक जुलाई से शुरू होगा। पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण विकास विभाग लेगा।

विश्व पर्यावरण दिवस 2025

विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करता है। अतः सभी स्वयंसेवी संस्थाएं इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

सरकार सुधारेगी अब गांवों की सेहत

राज्य सरकार गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 10 पैरामीटर तय किए है।

संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, प्रसव से पहले 100 प्रतिशत स्क्रीनग, टीबी और टोबेको मुक्त ग्राम पंचायत, मोतियाबिंद की जांच एवं उपचार जैसे दस स्वास्थ्य इंडीकेटर पर खरा उतरने पर सरकार ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एवं प्रमाण-पत्र देगी। इसमें गांव की जनता से सरपंच का सीधा संपर्क बढ़ेगा।

आवास योजना में मिलेंगे पक्के घर

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 22 लाख 23 हजार आवास बनाने के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। इनमें से करीब 20 लाख से अधिक आवासों का काम लगभग पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से पक्के घर का इंतजार कर रहे ग्रामीण परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। प्रदेश के 2 लाख 23 हजार से ज्यादा परिवारों को शीघ्र ही पक्के आवासों की सोगात मिलेगी। मुख्यमंत्री केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से लगातार समन्वय बनाकर अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश को दिलवाने के प्रयासों में लगे हैं।

महिला रोजगार संसाधन में प्रदेश आगे

देशभर में महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। राज्य में महिलाओं के लिए 89.38 फीसदी रोजगार संसाधन उपलब्ध हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात 71.43% और दिल्ली 51.85% के साथ तीसरे नंबर पर है।

इसके साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में राजस्थान 43% के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 42% के साथ तीसरे स्थान पर है। इस मामले में उत्तर प्रदेश 45% के साथ सबसे आगे है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट-2025 में राज्यों की यह तस्वीर निकल कर सामने आई है। रोजगार उपलब्ध कराने में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

जैसा कि विदित है ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इसी क्रम में इस साल 'सेहत पर भारी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ एवं प्रोसेस्ड फूड' विषय पर प्रविष्ठियाँ आमन्त्रित की गई। प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से जयपुर जिले के स्वतंत्र पत्रकार बाबूलाल कांकरेलिया को वर्ष 2024 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। बाबूलाल कांकरेलिया पुत्र रमाशंकर कांकरेलिया जयपुर जिले के भानपुर कला गांव के निवासी है तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं पंजाब केसरी में उनके लेख/खबरें प्रकाशित होती है।उन्हें दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर